



1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार द्वीपसमूह में पर्यावरण संबंधी मंजूरियों को लेकर बदलाव किया गया है।
2. कृषि अवसंरचना कोष के तहत, किसानों को कटाई पश्चात प्रबंधन और निवेश के लिए ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाएगी।
3. राष्ट्रीय वयोश्री और ADIP योजना के तहत मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए निशुल्क मूल्यांकन शिविरों के आयोजन किए जाएंगे।
4. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 'पौष्टिक लड्डू वितरण पहल' की शुरुआत की गई।



पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में उद्योगों और व्यापारिक इकाइयों के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरियों को लेकर बदलाव किया गया है। अब सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए द्वीपसमूह में यूसीएमएस पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। अब से स्थापना की सहमति, संचालन की सहमति और विभिन्न अन्य प्राधिकरणों के अनुदान या नवीनीकरण के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ये नियम द्वीपसमूह के सभी औद्योगिक इकाइयों, परियोजना प्रस्तावकों, उद्यमियों और अन्य संबंधित हितधारकों पर लागू होंगे। सभी संबंधित उद्यमियों और हितधारकों से समय पर स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए ucams.cpcb.gov.in पर पंजीकरण करने को कहा गया है। यह पोर्टल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत मिलने वाली मंजूरियों को पारदर्शी और त्वरित बनाना है।



केंद्रीय क्षेत्र की योजना – कृषि अवसंरचना कोष के तहत, देश में कृषि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कटाई के बाद के प्रबंधन और निवेश के लिए

माध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाती है। यह वित्तपोषण सुविधा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लाभार्थियों को ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, किसान और संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी और स्टार्टअप्स शामिल हैं। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज छूट मिलेगी। यह छूट अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर लागू होगी और 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान अपने संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारियों या कृषि निदेशालय के किसान कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।



राष्ट्रीय वयोश्री और ADIP योजना के तहत द्वीपसमूह में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए निशुल्क मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ADIP योजना के लाभार्थियों के पास न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का वैध UDID कार्ड होना, और उनकी मासिक आय 22,500 से कम होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आने वाले आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक और उनकी मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। शिविर बाईस जून को ब्रुक्शाबाद में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा फरारगंज में 23, बाराटांग में 25, रंगत में 26, मायाबंदर जिला अस्पताल में 27 और 28 जून को डिगलीपुर के चिकित्सा केन्द्रों पर लगेगा।



प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर द्वीपसमूह में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष जांच गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय 'प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष-सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माताएं, मजबूत भारत' था। इस अवसर पर पूरे द्वीपसमूह में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में, डॉ. आर.पी. अस्पताल, मायाबंदर में 10 वर्षीय उत्सव और गर्भवती महिलाओं के लिए 'पौष्टिक लड्डू वितरण पहल' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श और काउंसलिंग सेवाएं और पोषण किट का वितरण किया गया।



विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 'जलवायु कार्रवाई' विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में विभिन्न प्रशासनिक विभागों और संस्थानों ने मिलकर 18,068 पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशक, राकेश दास द्वारा कार्यालय परिसर में पौधा लगाकर किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए यूसीएमएस पोर्टल की शुरुआत की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सदस्य सचिव-सह-निदेशक ने यूनिफाइड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन **Management** सिस्टम पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने की आधिकारिक घोषणा की।



समाचार पत्रों की सुर्खियां

ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के तहत ग्रेट निकोबार द्वीप पर नया हवाई अड्डा और रनवे के निर्माण में 13 हजार करोड़ रुपये के निवेश करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। इसके अलावा अखबार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने के समाचार को भी प्रमुखता से छापा है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने एनआईओटी निदेशक द्वारा द्वीपसमूह में समुद्री कृषि और अवलोकन सुविधाओं की समीक्षा करने के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। इंडो इंडिया ने आटो की ओर से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहीद द्वीप में एफएम टूर आयोजित करने के समाचार को पहले पन्ने पर छापा है, जबकि द इको ऑफ इंडिया लिखता है—प्रदेश भाजपा ने मोदी सरकार की 12 वर्षों की विकास पहलों पर प्रकाश डाला। कहा सरकार ने डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं ने देश को बदल दिया है।

